The ACHIEVERS IAS ACADEMY

THE HINDU

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 02 Oct , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	इसरो मार्च 2028 में शुक्र ग्रह पर 112 दिवसीय मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है
Page 06 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	असम जनजाति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 8 उत्पादों, जिनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं, को जीआई टैग दिया गया
Page 06 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग और शांति को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की
Page 12 Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था	F&O में उछाल सेबी निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा
समाचार में स्थान	माउंट एरेबस
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध : द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते	फ्रांस में कूटनीति, तकनीक और विविधता के लिए शिखर सम्मेलन

शुक्र ग्रह पर पहुंचने के लिए भारत का पहला मिशन, जो मार्च 2028 में प्रक्षेपित किया जाना है, 112 दिनों की यात्रा पर निकलेगा।

ISRO plans to launch 112-day mission to the planet Venus in March 2028

The Hindu Bureau
BENGALURU

India's maiden mission to Venus, which is scheduled for launch in March 2028, will embark on a 112-day journey to reach the planet. The ₹1,236-crore Venus Orbiter Mission (VOM) was recently approved by the Union Cabinet and the Indian Space Research Organisation (ISRO) on Tuesday revealed the targeted launch window for the mission.

According to the targeted launch window for VOM, the Earth departure date is scheduled on March 29, 2028, and the arrival date on Venus is July 19, 2028. VOM will be launched by the Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3).

"LVM-3 has been identified as the candidate launch vehicle which will place the spacecraft in an Elliptical Parking Orbit (EPO) of 170 km x 36,000 km, 21.5 degrees inclination and Argument of Perigee (AOP) of 178 degrees. Minimum energy requirement (expressed as incremental velocity, V) for the launch opportunity that exists in 2028 for placing a spacecraft in an elliptical orbit of 500 x 60,000 km around Venus," ISRO said.

The agency said that after the cruise phase, Venus Orbit Injection (VOI) will be at 500 km x 60,000 km. "Aerobraking will be employed for over a period of six to eight months from VOI to achieve the desired low altitude Science Orbit of 200 X600 km with an inclination of around 90 degrees, to carry out proposed science studies for a period of five years," it said.

LVM-3 is the chosen launch vehicle for the mission: ISRO

ISRO said that 19 payloads will be onboard VOM, of which 16 are Indian payloads, two are Indian and international collaborative payloads, and there would be one international payload. ISRO added that VOM will explore the planet's atmosphere, surface and its interaction with the sun.

"Key objectives include examining dust in the Venusian atmosphere, mapping its topography in high resolution, studying the solar X-ray spectrum near Venus, analysing Venusian airglow, and investigating sub-surface characteristics. ," it added.

वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) के बारे में:

- लॉन्च वर्ष: मार्च 2028 के लिए निर्धारित।
- उद्देश्य: मिशन का उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल, सतह और सौर अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना है। मुख्य उद्देश्यों में शुक्र की स्थलाकृति का मानचित्रण, वायुमंडलीय संरचना का विश्लेषण, सौर एक्स-रे का अध्ययन और उपसतह विशेषताओं की जांच करना शामिल है।

स्वीकृत बजट: ₹1,236 करोड़

- लॉन्च वाहन: लॉन्च वाहन मार्क-3 (LVM-3)
- लक्षित विंडो: पृथ्वी से प्रस्थान की तिथि 29 मार्च, 2028 निर्धारित है, और शुक्र पर आगमन की तिथि 19 जुलाई, 2028 है

विशेषताएँ:

o 19 पेलोड (16 भारतीय, 2 भारतीय-अंतर्राष्ट्रीय, 1 अंतर्राष्ट्रीय)।
o कम ऊंचाई वाली विज्ञान कक्षा (200×600 किमी) प्राप्त करने के लिए एयरोब्रेकिंग तकनीक।
o कक्षा में प्रवेश के बाद पाँच साल की वैज्ञानिक अन्वेषण अवधि।

शुक्र से संबंधित अन्य मिशन

- **पिछले मिशन:**

o वेनेरा सीरीज (1961-1984): सोवियत संघ के सफल शुक्र मिशनों की श्रृंखला जिसमें फ्लाईबाई, ऑर्बिटर, लैंडर और गुब्बारे शामिल हैं।
o पायनियर वीनस (1978): नासा मिशन ने रडार का उपयोग करके शुक्र के वायुमंडल, बादल संरचना और सतह का अध्ययन किया।
o मैगलन (1989): नासा मिशन ने रडार इमेजिंग का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्रण किया।
o अकात्सुकी (2010): JAXA मिशन ने शुक्र के वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन किया।

- **भविष्य के मिशन:**

o वेरिटास (2026): शुक्र के भूविज्ञान का मानचित्रण करने के लिए नासा रडार मिशन।
o डेविन्सी (2026): शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा मिशन।
o एनविज़न (2030): शुक्र की सतह का मानचित्रण करने वाला ईएसए रडार मिशन।

- **LVM 3**
- **LVM-3 में 3 चरण हैं,**

o पहला (या सबसे निचला चरण) रॉकेट बॉडी के किनारों पर 2 S200 बूस्टर पट्टियों के रूप में है। वे हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन नामक एक ठोस ईंधन का दहन करते हैं,
o दूसरा चरण विकास इंजन द्वारा संचालित होता है, जो एक तरल ईंधन, या तो नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड या असममित डाइमिथाइलहाइड्राजिन का दहन करता है।
o सबसे ऊपरी अंतिम चरण एक क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होता है। यह द्रवित हाइड्रोजन को द्रवित ऑक्सीजन के साथ जलाता है।

- **यह निचली पृथ्वी की कक्षा में 8 टन तक उठा सकता है।**
- **लॉन्च किए गए LVM 3 मिशनों में से कुछ हैं,**

o वनवेब इंडिया-2 मिशन
o वनवेब इंडिया-1 मिशन
o चंद्रयान-2 मिशन
o GSAT-29 मिशन
o GSAT-19 मिशन
o CARE मिशन

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने असम के आठ उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बीयर की कई अनूठी किस्में शामिल हैं।

8 products used by Assam tribe, including traditional food items, granted GI tag

Sangeetha Kandavel
CHENNAI

The Geographical Indications Registry in Chennai has granted the GI tag to eight products from Assam, including traditional food items and several unique varieties of rice beer.

The application for Geographical Indication tags for three variants of rice beer was filed by the Bodo Traditional Brewers Association.

The first variant, 'Bodo Jou Gwran', has the highest percentage of alcohol (about 16.11%) compared with other varieties of rice beer made by the Bodo community.

The second variant, 'Maibra Jou Bidwi', known locally as 'Maibra Jwu Bidwi' or 'Maibra Zwu Bidwi', is revered and served as a welcome drink by most Bodo tribes. It's prepared by fermenting half-cooked rice (*mairong*) with less water, and adding a little '*amao*' (a potential source of yeast) to it.

A GI tag has been secured by 'Bodo Napham', a dish prepared with fermented fish

The third variant, called 'Bodo Jou Gishi', is also a traditionally fermented rice-based alcoholic beverage.

The GI filing states Bodoland has had a tradition of consuming rice beer since times immemorial. The Bodo people believe the drink originated from Lord Shiva, and it's taken as a medicine.

The Association of Traditional Food Products applied for four GI tags and obtained them successfully. A GI tag has been secured by 'Bodo Napham', a dish prepared with fermented fish.

A GI tag has also been secured by 'Bodo Ondla', a rice powder curry flavoured with garlic, ginger, salt, and alkali.

The 'Bodo Gwkha' has also received the GI tag. Locally also known as 'Gwka Gwkhi', it's prepared during the Bwisagu festival.

The fourth speciality given the GI tag is 'Bodo Narzi', a semi-fermented food prepared with jute leaves (*Corchorus capsularis*), a rich source of Omega 3 fatty acids, vitamins and essential minerals, including calcium and magnesium.

The 'Bodo Aronai', a small, beautiful cloth, also has the GI tag following the application by the Association of Traditional Bodo Weavers.

- बोडो समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली चावल की बीयर की अन्य किस्मों की तुलना में पहले प्रकार, 'बोडो जौ ग्वारन' में अल्कोहल का प्रतिशत सबसे अधिक (लगभग 16.11%) है।
- दूसरा प्रकार, 'मैबरा जौ बिडवी', जिसे स्थानीय रूप से 'मैबरा जू बिडवी' या 'मैबरा जू बिडवी' के रूप में जाना जाता है, अधिकांश बोडो जनजातियों द्वारा सम्मानित और स्वागत पेय के रूप में परोसा जाता है।

- इसे कम पानी के साथ आधे पके हुए चावल (मैरोंग) को किण्वित करके और उसमें थोड़ा 'अमाओ' (खमीर का एक संभावित स्रोत) मिलाकर तैयार किया जाता है।
- तीसरा प्रकार, जिसे 'बोडो जौ गिशी' कहा जाता है, भी पारंपरिक रूप से किण्वित चावल आधारित मादक पेय है।
- जीआई फाइलिंग में कहा गया है कि बोडोलैंड में प्राचीन काल से चावल की बीयर पीने की परंपरा रही है।
- बोडो लोगों का मानना है कि यह पेय भगवान शिव से उत्पन्न हुआ है, और इसे दवा के रूप में लिया जाता है।
- एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स ने चार जीआई टैग के लिए आवेदन किया और उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त किया। किण्वित मछली से तैयार व्यंजन 'बोडो नेफम' को जीआई टैग मिला है।
- लहसुन, अदरक, नमक और क्षार से बने चावल के पाउडर से बनी करी 'बोडो ओंडला' को भी जीआई टैग मिला है।
- 'बोडो ग्वखा' को भी जीआई टैग मिला है। स्थानीय रूप से इसे 'ग्वका ग्वखी' के नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्विसागु उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है।
- जीआई टैग पाने वाली चौथी खासियत है 'बोडो नार्जी', जो जूट के पत्तों (कोरकोरस कैप्सुलरिस) से बना अर्ध-किण्वित भोजन है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और कैल्शियम और मैग्नीशियम सहित आवश्यक खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है।
- पारंपरिक बोडो बुनकरों के संघ द्वारा आवेदन किए जाने के बाद 'बोडो अरोनाई', एक छोटा, सुंदर कपड़ा भी जीआई टैग प्राप्त कर चुका है।

- **भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बारे में:**
  - o जीआई टैग एक नाम या चिह्न है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से मेल खाते हैं।
  - o जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति रखते हैं।
  - o यह उत्पाद को दूसरों द्वारा कॉपी या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है।
  - o पंजीकृत जीआई 10 वर्षों के लिए वैध होता है।
  - o जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा की जाती है।

- **कानूनी ढांचा और दायित्व:**
  - o वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - o यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ समझौते (टीआरआईपीएस) द्वारा शासित और निर्देशित है।
  - o इसके अलावा, बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) और 10 में स्वीकार किया गया है और इस पर जोर दिया गया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान कहा कि फ्रांस शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करता है। डोभाल भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता के लिए पेरिस में थे।

India and France discuss defence cooperation and efforts to advance peace

Dinakar Peri
NEW DELHI

France appreciates Prime Minister Narendra Modi's initiatives to advance peace, French President Emmanuel Macron said on Tuesday, while meeting National Security Adviser Ajit Doval, who was in Paris for the India-France Strategic Dialogue.

Mr. Doval also discussed India's plans to procure French planes and submarines for the Navy during talks with his counterpart, the French President's Diplomatic Adviser Emmanuel Bonne, as well as French Armed Forces Minister Sebastien Lecornu. Sources have confirmed that France had agreed to a "significant reduction" in the cost of 26 Rafale-M fighters.

"[Mr. Doval] reiterated the commitment to implement the Horizon 2047," the Indian Embassy in France said in a post, adding that Mr. Macron had "stressed the value of India and France's efforts to advance peace and address global challenges; appreciated Mr. Modi's initiatives". While the reference to the peace initiatives is mainly in relation to the Russia-Ukraine conflict, and New Delhi's efforts to mediate between Kyiv and Moscow, the NSA's visit came even as Israel announced its ground invasion of Lebanon. In the past few days, Mr. Macron has spoken to the U.S. President Joe Biden, asking him to put pressure on Israel to stop its advances into Lebanon.

National Security Adviser Ajit Doval with French President Emmanuel Macron in Paris on Tuesday. PTI

भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **संबंध के स्तंभ:**
  - o भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। 1998 में हस्ताक्षरित भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी ने समय के साथ महत्वपूर्ण गति पकड़ी है और आज यह सहयोग के विविध क्षेत्रों में फैले एक और भी करीबी बहुआयामी संबंध के रूप में विकसित हुई है।

- **दोनों देशों ने रिश्ते में तीन स्तंभों को बनाए रखा है:**
  - o आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए आपसी सम्मान।
  - o रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता।
  - o संबंधित गठबंधनों और गठबंधनों में एक-दूसरे को शामिल करने से परहेज करने का साझा रुख।

- **रक्षा साझेदारी:**
  - o भारत-फ्रांस संबंधों के मूल में रक्षा साझेदारी है; अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में फ्रांस कहीं अधिक इच्छुक और उदार भागीदार के रूप में सामने आता है।
  - o राफेल सौदे से लेकर विमानों के 26 समुद्री संस्करणों के अधिग्रहण तक, फ्रांसीसी भारतीयों को अपनी कुछ बेहतरीन रक्षा प्रणालियाँ देने के लिए तैयार रहे हैं।
  - o फ्रांस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारत को पहले ही छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण में मदद मिली है, तथा नौसेना की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए अब तीन और पनडुब्बियाँ खरीदी जा रही हैं।
  - o संयुक्त अभ्यास: अभ्यास शक्ति (सेना), अभ्यास वरुण (नौसेना), अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)।

- **नाटो+ (प्लस) पर रुख में समानता:**
  - o फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)-प्लस (नाटो+) साझेदारी योजनाओं को अस्वीकार करता है, जिसके तहत ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि भारत के साथ सीधे संबंध बनाएगा।
  - o भारत ने भी इस योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि नाटो "भारत पर लागू होने वाला टेम्पलेट नहीं है"।

- **आर्थिक सहयोग:**
  - o दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 13.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया, जिसमें भारत से निर्यात 7 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया।
  - o फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2022 तक 10.49 बिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी निवेश किया है।

- **अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग:**
  - o फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन करता है और साथ ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में इसके प्रवेश का भी समर्थन करता है।

- **जलवायु सहयोग:**
  - o दोनों देश जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित हैं, और भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पेरिस समझौते में फ्रांस का समर्थन किया है।
  - o दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर अपने संयुक्त प्रयासों के हिस्से के रूप में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया।

- **भारत-फ्रांस संबंधों के बीच चुनौतियाँ**
- **FTA और BTIA में गतिरोध:**
  - o फ्रांस और भारत के बीच FTA (मुक्त व्यापार समझौता) की अनुपस्थिति उनकी व्यापार क्षमता को अधिकतम करने में बाधा डालती है।

o इसके अतिरिक्त, भारत-यूरोपीय संघ व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) पर धीमी प्रगति व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में चुनौतियों को और बढ़ा देती है।

रक्षा और सुरक्षा संबंधी भिन्न प्राथमिकताएँ:

o एक मजबूत रक्षा साझेदारी के बावजूद, प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों में अंतर रक्षा और सुरक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकता है।

o भारत का क्षेत्रीय फोकस और इसकी "गुटनिरपेक्ष" नीति कभी-कभी फ्रांस के वैश्विक हितों से टकरा सकती है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की चिंताएँ:

o फ्रांस ने भारत द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की अपर्याप्त सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है, जिसका असर भारत में संचालित फ्रांसीसी व्यवसायों पर पड़ रहा है। यह द्विपक्षीय व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

व्यापार असंतुलन और रक्षा उत्पादों का प्रभुत्व:

o हालाँकि फ्रांस भारत का 11वाँ व्यापार भागीदार है, लेकिन एक उल्लेखनीय व्यापार असंतुलन है।

o व्यापार संबंधों में रक्षा उत्पादों का प्रभुत्व विविधीकरण और अधिक संतुलित आर्थिक विनिमय प्राप्त करने के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

फ्रांस में भारतीय उत्पादों के लिए बाधाएँ:

o भारत को फ्रांस को अपने उत्पादों के निर्यात में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपायों के संदर्भ में। यह फ्रांसीसी बाजार में भारतीय उत्पादों के प्रवेश को हतोत्साहित कर सकता है।

छात्र आवागमन:

o जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने की योजना की घोषणा की है, वीजा प्रक्रिया और सांस्कृतिक एकीकरण सहित छात्र आवागमन से संबंधित मुद्दे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

मानव तस्करी की चिंताएँ:

o मानव तस्करी से जुड़े निकारागुआ फ्लाइट मामले जैसे उदाहरण चिंताएँ बढ़ाते हैं और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने और व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उच्च जोखिम वाले वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) बाजार में खुदरा भागीदारी को कम करने के उद्देश्य से छह नए नियम पेश किए हैं।

F&O spike: SEBI to step in to guard investors

Press Trust of India
NEW DELHI

Capital markets regulator SEBI is expected to take measures regarding the Futures and Options (F&O) segment very soon, in a bid to enhance investor protection, a senior official said on Tuesday.

In addition, SEBI has urged the government to introduce tax breaks for subscribers of municipal bonds, which are crucial for funding infrastructure development.

The regulator will make a case for a tax break for municipal bonds during a meeting with the finance commission, the regulator's whole time member Ashwani Bhatia said here.

Since 1997, municipalities have raised ₹2,700 crore through bonds for infrastructure projects.

Talking about F&O, Mr. Bhatia said, "SEBI is very soon going to do something about F&O". In its consultation paper, the regulator had suggested to revise the minimum contract size for index derivatives in two phases, considering market growth.

F&O के बारे में:

- वायदा और विकल्प (F&O) व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं जो स्टॉक, कमोडिटी या सूचकांक जैसे अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।

- भारतीय शेयर बाजार में इनका व्यापक रूप से कारोबार होता है, मुख्य रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) जैसे एक्सचेंजों पर।
- जोखिमों से बचाव, अटकलें लगाने या पोर्टफोलियो रणनीतियों को बढ़ाने के इच्छुक निवेशकों के लिए F&O को समझना महत्वपूर्ण है।
- भारत में, F&O ट्रेडिंग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।

व्युत्पन्न क्या हैं?

- व्युत्पन्न वित्तीय अनुबंध हैं जिनका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति पर निर्भर करता है, जो इक्विटी, सूचकांक, कमोडिटी या मुद्राएं हो सकती हैं।
- F&O भारत में व्युत्पन्न अनुबंधों के दो सबसे लोकप्रिय प्रकार हैं।

वायदा के बारे में:

- वायदा अनुबंध किसी परिसंपत्ति को किसी निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का एक कानूनी समझौता है।
- खरीदार और विक्रेता दोनों ही अनुबंध की परिपक्वता के समय मौजूदा बाजार मूल्य की परवाह किए बिना, सहमत मूल्य पर लेनदेन को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- मानकीकृत अनुबंध: वायदा अनुबंध मात्रा, गुणवत्ता और डिलीवरी समय के मामले में मानकीकृत होते हैं।
- उत्तोलन: निवेशक मूल्य का एक अंश, जिसे मार्जिन के रूप में जाना जाता है, लगाकर बड़ी मात्रा में परिसंपत्तियों का व्यापार कर सकते हैं। यह उत्तोलन प्रदान करता है लेकिन जोखिम भी बढ़ाता है।
- मार्क-टू-मार्केट: वायदा अनुबंधों को प्रतिदिन बाजार में चिह्नित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में लाभ और हानि की गणना की जाती है।
- निपटान: भारत में, अधिकांश वायदा अनुबंधों का निपटान नकद में किया जाता है, लेकिन कुछ कमोडिटी वायदा में भौतिक डिलीवरी शामिल हो सकती है।

उदाहरण:

- यदि आप 19,000 पर निफ्टी 50 वायदा अनुबंध खरीदते हैं और अनुबंध की समाप्ति तक बाजार 19,500 तक बढ़ जाता है, तो आपको प्रति यूनिट ₹500 का लाभ होता है।
- इसके विपरीत, यदि बाजार 18,500 तक गिर जाता है, तो आपको प्रति यूनिट ₹500 का नुकसान होता है।

विकल्पों के बारे में:

- विकल्प अनुबंध धारक को अनुबंध की समाप्ति तिथि से पहले या उस दिन पूर्व निर्धारित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं। विकल्प दो प्रकार के होते हैं: कॉल विकल्प और पुट विकल्प।

कॉल विकल्प:

- कॉल विकल्प खरीदार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने का अधिकार देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब निवेशकों को परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि की उम्मीद होती है।

पुट विकल्प:

- पुट विकल्प खरीदार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति बेचने का अधिकार देता है। निवेशक इसका उपयोग तब करते हैं जब उन्हें परिसंपत्ति की कीमत में गिरावट की उम्मीद होती है।

प्रीमियम:

- कॉल और पुट दोनों विकल्पों में, खरीदार विकल्प का प्रयोग करने के अधिकार के लिए विक्रेता (लेखक) को प्रीमियम का भुगतान करता है। प्रीमियम विकल्प खरीदने की लागत है।

उदाहरण:

- कॉल विकल्प: मान लीजिए कि आप ₹2,500 की स्ट्राइक कीमत के साथ रिलायंस स्टॉक पर कॉल विकल्प खरीदते हैं। यदि विकल्प की समाप्ति से पहले रिलायंस के शेयर की कीमत ₹2,700 तक बढ़ जाती है, तो आपको इसे ₹2,500 पर खरीदने का अधिकार है, जिससे आपको प्रति शेयर ₹200 का लाभ होगा।
- पुट ऑप्शन: यदि आप उसी शेयर के लिए ₹2,500 के स्ट्राइक मूल्य पर पुट ऑप्शन खरीदते हैं, और कीमत ₹2,300 तक गिर जाती है, तो आप इसे ₹2,500 पर बेच सकते हैं, जिससे आपको प्रति शेयर ₹200 का लाभ होगा।

सेबी ने एफएंडओ नियमों को सख्त किया:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उच्च जोखिम वाले वायदा और विकल्प (एफएंडओ) बाजार में खुदरा भागीदारी को कम करने के उद्देश्य से छह नए नियम पेश किए हैं। परिवर्तनों में शामिल हैं:
  - o न्यूनतम अनुबंध मूल्य को बढ़ाकर ₹15 लाख करना,
  - o विकल्प प्रीमियम का अग्रिम भुगतान आवश्यक बनाना,
  - o प्रति एक्सचेंज साप्ताहिक समाप्ति को एक तक सीमित करना, और
  - o अनुबंधों की समाप्ति के करीब आने पर मार्जिन बढ़ाना।
- विनियमनों को चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण के बदलाव, जिसमें अनुबंध का आकार बढ़ाना और समाप्ति के दिन शॉर्ट ऑप्शन के लिए हानि मार्जिन में 2% की वृद्धि शामिल है, 20 नवंबर, 2024 को प्रभावी होंगे।
- कैलेंडर स्प्रेड लाभों को हटाने जैसे अतिरिक्त उपाय 1 फरवरी, 2025 से शुरू होंगे और इंट्रा-डे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होगी।
- ये कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय द्वारा खुदरा निवेशकों द्वारा सट्टा F&O ट्रेडों में पर्याप्त घरेलू बचत खोने के बारे में उठाई गई चिंताओं के बाद की गई है।
- सेबी के एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 93% खुदरा व्यापारियों को औसतन ₹2 लाख का नुकसान हुआ, जिससे वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 24 के बीच कुल शुद्ध घाटा ₹1.81 ट्रिलियन हो गया।
- जबकि विनियमन का उद्देश्य बाजार जोखिम प्रबंधन को बढ़ाना और सट्टा व्यवहार पर अंकुश लगाना है, ब्रोकरेज फर्मों और स्टॉक एक्सचेंजों को F&O ट्रेडिंग वॉल्यूम में 30-40% की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

Location In News : Mount Erebus

अंटार्कटिका में माउंट एरेबस, सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो न केवल अत्यधिक ठंड में सक्रिय रहता है, बल्कि सोने के सूक्ष्म क्रिस्टल उत्सर्जित करने के कारण भी प्रसिद्ध है।

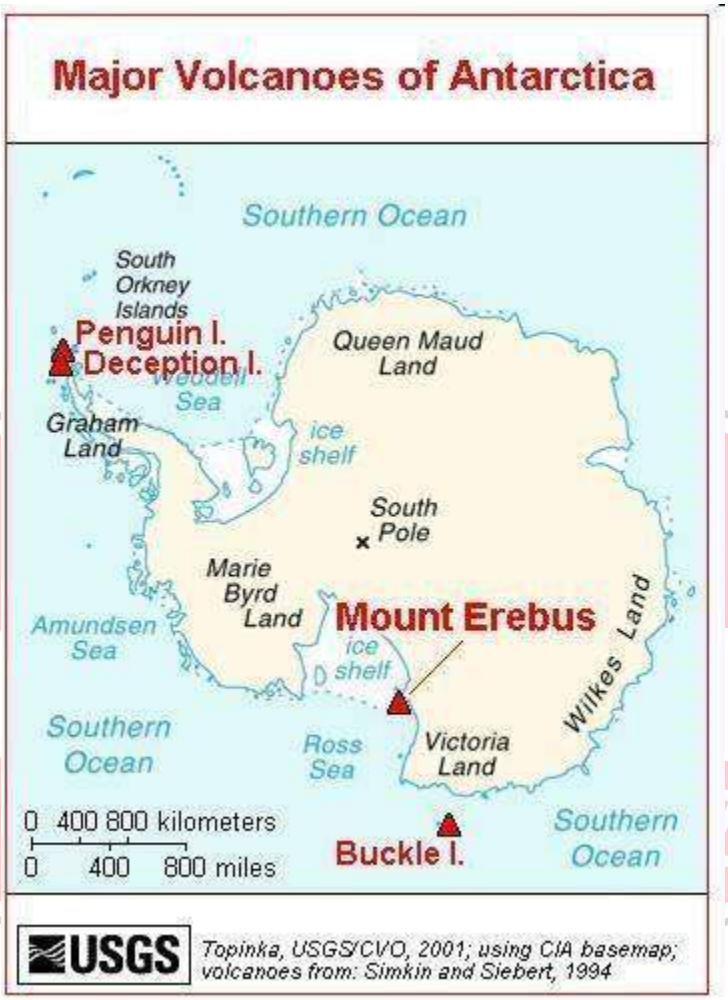

माउंट एरेबस के बारे में:

- स्थान: रॉस द्वीप, अंटार्कटिका; पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी।
- ज्वालामुखी का प्रकार: स्ट्रेटोवोलकैनो, लावा और राख की परतों से बने शंक्वाकार आकार की विशेषता।
- खोज: 1841 में ब्रिटिश खोजकर्ता सर जेम्स क्लार्क रॉस द्वारा खोजा गया, जिसका नाम उनके जहाज एचएमएस एरेबस के नाम पर रखा गया।
- ऊँचाई: 3,792 मीटर (12,441 फीट) पर स्थित, अंटार्कटिका में दूसरा सबसे ऊँचा ज्वालामुखी।
- लावा झील: अपनी लगातार बनी रहने वाली लावा झील के लिए जानी जाती है, जो कम से कम 1972 से सक्रिय है, यह दुनिया भर में कुछ लंबे समय तक रहने वाली लावा झीलों में से एक है।
- विस्फोट: इसमें स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट होते हैं, जिसमें कभी-कभी पिघले हुए लावा बम निकलते हैं।
- अनुसंधान स्टेशनों से निकटता: मैकमुर्डो स्टेशन (यू.एस.) और स्कॉट बेस (न्यूजीलैंड) से इसकी निकटता (40 किमी) के कारण इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 08 Editorial Analysis

In France, a summit for diplomacy, tech and diversity

Thierry Mathou

the Ambassador of France to India

France will host over 100 Heads of states and government and high-ranking officials for the 19th Francophonie Summit on October 4-5, 2024. The summit will take place in Paris and in Villers-Cotterêts, a city where, in 1539, King François I declared French as the country's official language. It will deal with a number of key international questions that also matter to many non-French-speaking countries, and especially to India. These include the renewal of multilateralism; and major digital issues linked to the development of Artificial Intelligence (AI) as well as the need to promote cultural and linguistic diversity.

As the famous Senegalese President and poet Léopold Sédar Senghor said, "Francophonie is the integral Humanism." One of the key messages of the summit will be that: far from being barriers or creating divides, multilingualism and cultural diversity foster mutually beneficial exchanges and collective thinking, and, as such, should be cherished. I have every reason to believe that this spirit, shared by 321 million French speakers across the world, including Puducherry (India), also resonates with India's own priorities.

Reducing the divide

Founded in 1970, the l'Organisation Internationale de la Francophonie (the International Organization of La Francophonie) is an institution organising relations between countries that use the French language. Prominent statesmen such as Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba (Tunisia), Hamani Diori (Niger) and Norodom Sihanouk (Cambodia) were among its founding fathers.

The aim of the organisation is to promote the French language and cooperation between its 88 Member States and Governments (54 full-fledged members, seven associate members and 27 observer members). This aim is enshrined in the Charter of La Francophonie, adopted in 1997 at the Hanoi Summit. From the outset, the organisation has been a forum of discussions and projects between countries boasting diverse cultures, economic and geographic situations as well as different political orientations. Francophonie has been promoting democracy, peace, prosperity with the idea of reducing any so-called "North/South divide" as well as bolstering cultural and linguistic diversity. Today, La Francophonie also provides a cooperation framework for key global issues such as digital technology, gender equality, and economic matters, under the leadership of Secretary General Louise Mushikiwabo, former Rwandan Minister for Foreign Affairs.

The 19th Francophonie Summit has priorities that will resonate with those of India's

Renewing multilateralism

In the face of a fragmented world, the Summit, which takes place every two years under the leadership of a rotating host country, is meeting to decide on the main orientations of the organisation. For the first time in 33 years, the summit will be hosted by France. Upholding "Create, Innovate and do Business in French", the theme, a new method of discussion will be followed during the Summit. Civil society stakeholders will be able to exchange more directly with summit officials to promote solutions and explore new avenues for cooperation.

Heads of states and high-ranking officials will deliberate in Paris on how to renew multilateralism. As France's President Emmanuel Macron has stated in his speech at the 79th United Nations General Assembly, the renewal of multilateralism implies that we must change the governance composition of our main institutions. This is the reason why France supports the bid by India and other G-4 nations for a permanent seat in the United Nations Security Council. We need to make our international institutions more efficient, which also means making them more representative. Beyond that, we need to work on a common financial agenda and to thoroughly reform the World Bank and the International Monetary Fund.

As President Macron has pointed out: "These institutions were conceived, designed and calibrated at a time when the challenges were not the same, when the world economy was not the same size, when demographics had nothing to do with it. We need to give these institutions the capacity to act to finance the projects that the countries of the South need. This reform is imperative for our collective credibility." As we need to build an agenda that allows us to tackle climate change, biodiversity preservation, global health issues, as well as reduce inequalities, France believes that La Francophonie can make an important contribution in this regard.

A focus on digital technology

The summit will also have a major focus on digital technology at a time when AI is proliferating in our societies. AI tools have raised new questions about the protection of creation and the promotion of diversity. Platforms must be able to enforce citizens' rights in their own language, while AI can also become a tremendous asset for French and all other languages, by facilitating translation. As it is one of the civilizational challenges of our century, France will follow up on these deliberations by hosting the AI Action Summit in February 2025.

On the margins of this summit, the first FrancoTech Fair, a major event that will bring together more than 150 exhibitors from various nations to discuss pressing challenges of our times, will be held. Topics will include opportunities and challenges in developing AI; energy transition; education, and, more broadly, human capital development. For young Indian innovators with international ambitions, this event will offer opportunities with Francophone actors from around the globe.

Multilateralism, innovation, AI, cultural and linguistic diversity. I believe that all these La Francophonie topics are of shared interest and importance for France and India. The Paris AI Action Summit in 2025 as well as the India-France Year of Innovation that will be launched in 2026 will be important moments to push forward new collective solutions in these fields.

GS Paper 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते

(UPSC CSE (M) GS-2 2022) : I2U2 (भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका) समूह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? (150 w /10 m)

UPSC Mains Practice Question : भारत-फ्रांस संबंधों के महत्व और बाधाओं पर चर्चा करें। उनके सहयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। (150 w /10 m)

संदर्भ :

- भारत और चीन में बढ़ती उम्रदराज आबादी चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करती है।
- स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती जरूरतें, वित्तीय असुरक्षाएं और डिजिटल बहिष्कार प्रमुख चिंताएं हैं जिनमें सुधार की जरूरत है।
- स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सहायता, डिजिटल समावेशन और "सिल्वर इकोनॉमी" के विकास के जरिए इन मुद्दों को संबोधित करके बुजुर्गों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

परिचय

- फ्रांस 4-5 अक्टूबर, 2024 को 19वें फ्रैंकोफोनी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार तथा उच्च पदस्थ अधिकारियों की मेजबानी करेगा।
- शिखर सम्मेलन पेरिस और विलर्स-कॉटेरेट्स में होगा, एक ऐसा शहर जहां 1539 में राजा फ्रांस्वा प्रथम ने फ्रेंच को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया था।
- यह कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सवालों से निपटेगा जो कई गैर-फ्रेंच भाषी देशों और खासकर भारत के लिए भी मायने रखते हैं।
- इनमें बहुपक्षवाद का नवीनीकरण शामिल है; और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास से जुड़े प्रमुख डिजिटल मुद्दों के साथ-साथ सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

फ्रैंकोफ़ोनी और सांस्कृतिक विविधता

- जैसा कि प्रसिद्ध सेनेगल के राष्ट्रपति और कवि लियोपोल्ड सेडर सेनघोर ने कहा, "फ्रैंकोफ़ोनी एकात्म मानवतावाद है।"
- शिखर सम्मेलन के मुख्य संदेश: यह होंगे: अवरोध बनने या विभाजन पैदा करने से दूर, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान-प्रदान और सामूहिक सोच को बढ़ावा देती है, और, इस तरह, इसे संजोया जाना चाहिए।
- भारत के हितों से मेल खाते हुए: मेरे पास यह मानने का हर कारण है कि पुडुचेरी (भारत) सहित दुनिया भर में 321 मिलियन फ्रेंच बोलने वालों द्वारा साझा की गई यह भावना भारत की अपनी प्राथमिकताओं के साथ भी प्रतिध्वनित होती है।

विभाजन को कम करना

- संगठन के बारे में: 1970 में स्थापित, l'Organisation Internationale de la Francophonie (अंतर्राष्ट्रीय संगठन ला फ्रैंकोफ़ोनी) एक संस्था है जो फ्रेंच भाषा का उपयोग करने वाले देशों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करती है।
- प्रसिद्ध संस्थापक सदस्य: लियोपोल्ड सेडर सेनघोर, हबीब बोरगुइबा (ट्यूनीशिया), हमानी डियोरी (नाइजर) और नोरोडोम सिहानोक (कंबोडिया) जैसे प्रमुख राजनेता इसके संस्थापक सदस्यों में से थे।

संगठन के मुख्य लक्ष्य

- फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देना: संगठन का उद्देश्य अपने 88 सदस्य देशों और सरकारों (54 पूर्ण सदस्य, सात सहयोगी सदस्य और 27 पर्यवेक्षक सदस्य) के बीच फ्रेंच भाषा और सहयोग को बढ़ावा देना है।
  o यह उद्देश्य 1997 में हनोई शिखर सम्मेलन में अपनाए गए ला फ्रैंकोफोनी के चार्टर में निहित है।
- समावेशी संगठन: शुरू से ही, संगठन विभिन्न संस्कृतियों, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक झुकाव वाले देशों के बीच चर्चाओं और परियोजनाओं का एक मंच रहा है।
- लोकतंत्र को बढ़ावा देना: फ्रैंकोफोनी किसी भी तथाकथित "उत्तर/दक्षिण विभाजन" को कम करने के विचार के साथ-साथ सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोकतंत्र, शांति, समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है।
- सहयोग को बढ़ावा देना: आज, ला फ्रैंकोफोनी महासचिव लुईस मुशिकीवाबो, पूर्व रवांडा विदेश मंत्री के नेतृत्व में डिजिटल प्रौद्योगिकी, लैंगिक समानता और आर्थिक मामलों जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों के लिए एक सहयोग ढांचा भी प्रदान करता है।

बहुपक्षवाद को नवीनीकृत करना

- शिखर सम्मेलन आयोजित करना: एक खंडित दुनिया के सामने, शिखर सम्मेलन, जो एक घूर्णनशील मेजबान देश के नेतृत्व में हर दो साल में होता है, संगठन के मुख्य अभिविन्यासों पर निर्णय लेने के लिए बैठक कर रहा है।
- फ्रांस का पहला मौका: 33 वर्षों में पहली बार, शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी।
- शिखर सम्मेलन का विषय और दृष्टिकोण: "फ्रेंच में बनाएँ, नवाचार करें और व्यापार करें" थीम को कायम रखते हुए, शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा की एक नई पद्धति का पालन किया जाएगा।
  o नागरिक समाज के हितधारक समाधानों को बढ़ावा देने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए शिखर सम्मेलन के अधिकारियों के साथ अधिक सीधे आदान-प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित करना: राष्ट्राध्यक्ष और उच्च-श्रेणी के अधिकारी पेरिस में इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि बहुपक्षवाद को कैसे नवीनीकृत किया जाए।
- जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा है, बहुपक्षवाद के नवीनीकरण का तात्पर्य है कि हमें अपने मुख्य संस्थानों की शासन संरचना को बदलना होगा।
- भारत के पक्ष में प्रेंस: यही कारण है कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत और अन्य जी-4 देशों की दावेदारी का समर्थन करता है।

बहुपक्षवाद का नवीनीकरण

- कई चुनौतियों से निपटना: जैसा कि राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया है: "इन संस्थानों की कल्पना, डिजाइन और अंशांकन ऐसे समय में किया गया था जब चुनौतियाँ समान नहीं थीं, जब विश्व अर्थव्यवस्था का आकार समान नहीं था, जब जनसांख्यिकी का इससे कोई लेना-देना नहीं था।
- क्षमता निर्माण और वित्त: हमें इन संस्थानों को उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता प्रदान करने की आवश्यकता है जिनकी दक्षिण के देशों को आवश्यकता है। यह सुधार हमारी सामूहिक विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है।"
- पर्यावरण पर ध्यान: चूंकि हमें एक ऐसा एजेंडा बनाने की आवश्यकता है जो हमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के साथ-साथ असमानताओं को कम करने की अनुमति दे, फ्रांस का मानना है कि ला फ्रैंकोफोनी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी पर ध्यान

- डिजिटल बढ़ावा: शिखर सम्मेलन में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भी एक प्रमुख ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसे समय में जब हमारे समाजों में एआई का प्रसार हो रहा है।
- विविधता को बढ़ावा देना: एआई उपकरणों ने सृजन की सुरक्षा और विविधता को बढ़ावा देने के बारे में नए सवाल उठाए हैं।
- अधिकारों को पूरा करना: प्लेटफ़ॉर्म को नागरिकों के अधिकारों को उनकी अपनी भाषा में लागू करने में सक्षम होना चाहिए, जबकि एआई अनुवाद की सुविधा देकर फ्रेंच और अन्य सभी भाषाओं के लिए एक जबरदस्त संपत्ति बन सकता है।
- चूंकि यह हमारी सदी की सभ्यतागत चुनौतियों में से एक है, इसलिए फ्रांस फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट की मेजबानी करके इन विचार-विमर्शों का अनुसरण करेगा।

आगे की राह:

- भारत के लिए अवसर इस शिखर सम्मेलन के दौरान, पहला फ्रैंकोटेक मेला आयोजित किया जाएगा, जो एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें हमारे समय की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के 150 से अधिक प्रदर्शक एक साथ आएंगे।
- विषयों में एआई के विकास में अवसर और चुनौतियाँ शामिल होंगी; ऊर्जा संक्रमण; शिक्षा, और, अधिक व्यापक रूप से, मानव पूंजी विकास।
- अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं वाले युवा भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए, यह कार्यक्रम दुनिया भर के फ्रैंकोफोन अभिनेताओं के साथ अवसर प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

- बहुपक्षवाद, नवाचार, एआई, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, ला फ्रैंकोफोनी विषय फ्रांस और भारत के लिए साझा रुचि और महत्व के हैं।
- 2025 में पेरिस एआई एक्शन समिट और साथ ही 2026 में शुरू होने वाला भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष इन क्षेत्रों में नए सामूहिक समाधानों को आगे बढ़ाने और अधिक समावेशी समाज सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षण होंगे।